विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1948
उत्तर की तिथि	:	05.03.2022
विषय	:	राष्ट्रीय उच्च मार्ग
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :–. (क) राष्ट्रीय उच्च मार्ग–05, रामपुर–भावानगर दयनीय हालत में है; इसकी रि–सरफेसिंग का कार्य किस वर्ष प्रस्तावित था तथा यह कार्य कब आरम्भ कर दिया जाएगा; और	जी नहीं, रामपुर भाबानगर सड़क की स्थिति दयनीय हालत में नहीं है। रामपुर से झाकड़ी तक रि–सरफेसिंग का कार्य वर्ष, 2020 में प्रस्तावित था जिस में से रामपुर से बरौनी (कि0मी0 275/00 से 284/00) की टारिंग का कार्य दिनांक 02.12.2021 को पूर्ण कर लिया गया है। बरौनी से झाखडी (कि0मी0 284/0 से 286/00) की टारिंग के कार्य की निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है जो 22.03.2022 को खोली जाएंगी । विभाग ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के झाखडी से सुंगरा तक के सुदृढ़ीकरण (pavement strengthing) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की है जिसमें टारिंग का कार्य भी शामिल है। उपरोक्त परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जा रहा है। स्वीकृति मिलने के उपरांत ही उपरोक्त कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

(ख) यह सत्य है कि इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बघाल से सोल्डिंग तक कई जगहों पर चौड़ाई व सुधार का कार्य होना शेष है; यदि हां, तो यह कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है; कारणों सहित ब्यौरा दें?	इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बघाल से सोल्डिंग तक कुछ स्थानों पर जहाँ ब्लास्टिंग के द्वारा कटान करके सड़क को चौड़ा किया जाना था वहां सड़क की चौड़ाई व सुधार का कार्य शेष है क्योंकि पिछले वर्ष सड़क के इस भाग में कई जगह बार–बार भारी भू–स्खलन होता रहा जिसके लिए ब्लास्टिंग को भी कारण माना जा रहा था इसलिए एहतियात के तौर पर ऐसी जगह पर ब्लास्टिंग करके सड़क को चौड़ा नहीं किया जा सका, लेकिन विभाग ने ज्यूरी से सोल्डिंग तक सड़क को सुदृढीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मु0 54.44 करोड़ की तैयार की है जिसमें सड़क की टारिंग भी शामिल है। इसमें सड़क के तंग भागों में किनारे से किनारे तक (edge to edge) टारिंग करने का प्रावधान रखा गया है, जिससे सड़क के carriageway की चौड़ाई को बढाया जायेगा। उपरोक्त परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जा रहा है। स्वीकृति मिलने के उपरांत उपरोक्त कार्य को पूर्ण कर दिया जायेगा ।